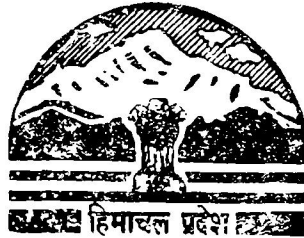


रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बोरवार, 28 मार्च, 2002/7 चैत्र, 1924

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 मार्च, 2002

संख्या 1-28/2002-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2002

(2002 का विधेयक संख्यांक-9) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,  
सचिव।

2002 का विधेयक संख्यांक 9.

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971  
(1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप  
में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2002 है। संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ।
- (2) यह अगस्त, 2002 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा।
2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 धारा 3 का  
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की संशोधन।  
उप-धारा (1) में, "सात सौ पचास" के स्थान पर एक हजार दो सौ पचास  
शब्द रखे जाएंगे।
3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का  
संशोधन।
  - (क) उप-धारा (1) के खण्ड (11) में, "तीन सौ" शब्दों के स्थान पर "चार  
सौ" शब्द रखे जाएंगे।
  - (ख) उप-धारा (2) में, "तीन सौ" शब्दों के स्थान पर "चार सौ शब्द रखे  
जाएंगे।
4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में, "चार हजार" धारा 5 का  
शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे। संशोधन।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यों को प्रतिकारात्मक भत्ते, विराम भत्ते और टेलीफोन भत्ते के रूप में क्रमशः सात सौ पचास रुपए प्रतिमास, तीन सौ रुपए प्रतिदिन और चार हजार रुपए प्रतिमास संदत्त किये जा रहे हैं। अब, विराम के दौरान उपगत तथा उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान या उसके स्थाई निवास स्थान पर या शिमला में स्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिकारात्मक भत्ते में सात सौ पचास रुपए से बारह सौ पचास रुपए प्रतिमास और विराम भत्ते में तीन सौ रुपए प्रतिदिन से चार सौ रुपए प्रतिदिन तथा टेलीफोन भत्ते में चार हजार रुपए से पांच हजार रुपए प्रतिमास की बढ़ोतरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश (विधान सभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 3, 4 और 5 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मंत्री।

शिमला :

.....मार्च, 2002.

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 4 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष 19.00 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या जी०ए०डी-सी० (पी०ए०) 6-2/2001.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) विधेयक, 2002 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Bill No. 9 of 2002.**

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2002**

**(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)**

**A**

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty third Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and pension of Members) Amendment Act, 2002.

Short title.  
and Com-  
mencement.

(2) It shall come into force on the first day of August, 2002.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "seven hundred and fifty", the words "one thousand two hundred and fifty", shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 3.

3. In section 4 of the principal Act,—

Amend-  
ment of  
section 4.

(a) in sub-section (1), in clause (ii), for the words "three hundred", the words "four thousand", shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "three hundred", the words "four hundred" shall be substituted.

4. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), in first proviso, for the words "four thousand", the words "five thousand" shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 5.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present Hon'ble Member of the State Legislative Assembly is paid compensatory allowance, halting allowance and telephone allowance @ Rs. 750/- per month, Rs. 300/- per day and Rs. 400/- per month respectively. Now, it has been decided to amend sections 3, 4 and 5 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, to increase the Compensatory allowance from Rs. 750/- to Rs. 1250/- per month, halting allowance from Rs. 300/- to Rs. 400/- and telephone allowance from Rs. 4000/- to Rs. 5000/- per month to meet the expenses increased during halt age and expenses of local and outside calls in respect of telephone, installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence or at Shimla. This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,  
Chief Minister.

SHIMLA :

The.....2002.

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer, to the tune of Rs. 19.00 lakh per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

NIL

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

File No. GAD-C-(PA)-6-2) 2001

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2002 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.